To Increase the Ground Water Level

137. Smt. Naina Singh Chautala, M.L.A.: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the steps taken by the Government to increase the underground water level in Badhra Assembly Constituency togetherwith the details thereof?

JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE & FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA

Sir, a statement has been laid on the table of the House.

Statement

To Increase the Ground Water Level

137. Smt. Naina Singh Chautala, M.L.A.

The steps taken by Agriculture and Farmers Welfare Department to increase the Ground Water level in Badhra Assembly Constituency and benefits given to farmers for adopting water conservation measures in Haryana are as under:-

1. "The Haryana State Preservation of Sub Soil Water Act, 2009" has been enacted which prohibits sowing of Paddy before 15th of May and transplanting of Paddy before 15th of June.
2. A State Plan Scheme namely "Accelerated Recharge of Ground Water" has been introduced from the year 2005-06 to recharge the ground water in water deficit areas of the State. Under this scheme, 953* numbers of Rain Water Harvesting structures have been constructed till 2019-20. In Badhra 08 number of Rain Water Harvesting structures has been constructed till 2019-20.
3. The Department encourages the farmers to adopt Drip Irrigation System. Subsidy @85% for all categories of farmers limited to 5 ha per beneficiary has been fixed. An amount of Rs. 2943.00 lakh has been spent on Drip Irrigation system to cover an area of 4819.19 hectares till 2019-20.

   In Badhra block of Charkhi Dadri district an amount of Rs. 44.44 lakh has been spent on Drip Irrigation System to cover an area of 60.64 hectares with 53 numbers of beneficiaries upto the month of July 2020.
4. The Department encourages the farmers to adopt Sprinkler Irrigation System. Subsidy @85% for all categories of farmers limited to 5 ha per beneficiary has been fixed. An amount of Rs. 28636.03 lakh has been spent on Sprinkler Irrigation system to cover an area of 674788.18 hectares till 2019-20.

   In Badhra block of Charkhi Dadri district an amount of Rs. 473.98 lakh has been spent on Sprinkler Irrigation System to cover an area of 1826.35 hectares with 1472 numbers of beneficiaries upto the month of July 2020.

5. To reduce seepage and evaporation losses, subsidy is being provided to the farmers for laying Underground Pipe Line System. Subsidy @50% to the cost of system limited to Rs. 25000/- per hectare with maximum of Rs. 60000/- per beneficiary is applicable. An amount of Rs. 35842.35 lakh has been spent for laying UGPL system to cover an area of 223695.21 hectares till 2019-20.

   In Badhra block of Charkhi Dadri district an amount of Rs. 93 lakh has been spent on UGPL system to cover an area of 501.69 hectares with 265 numbers of beneficiaries upto the month of July 2020.

6. Crop Diversification programmes have been launched in the State for conservation of natural groundwater resource, alternate crops e.g. maize, sunflower and summer moong etc. are being promoted in place of water guzzling paddy. During 2020-21 the program is launched as 'Mera Pani Meri Virasat' with the subsidy benefit of Rs. 7000.00 per acre will be provided to the farmers under the scheme.

7. Mass Awareness Campaigns are held from time to time to educate the farmers regarding conservation of groundwater and judicious use of irrigation water.

भू–जल स्तर बढ़ाना

137. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, एम0एल0ए0 : क्या कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि बाढ़डा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में भू–जल स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

———————————————————————————————————

जय प्रकाश दलाल, कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री, हरियाणा

महोदय, एक ब्यान सदन के पटल पर रखा गया है।

टिप्पणी

भू–जल स्तर बढ़ाना

137. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, एम0एल0ए0

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में गिरते भू–जल के स्तर की समस्या से निपटने तथा किसानों के हितों हेतू जल संरक्षण की पद्धतियों के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्य करवाये गये हैं :–

1. राज्य में 15 मई से पूर्व धान की बिजाई तथा 15 जून से पूर्व रोपाई की रोकथाम के लिये **"हरियाणा भूमिगत जल परिरक्षण अधिनियम, 2009"** नाम का विधेयक लागू किया गया है।
2. राज्य के गहरे भू–जल स्तर वाले क्षेत्रों में जल–रिचार्ज के लिये **"एकसेलेरेटिड रीचार्ज आफ ग्राउंड वाटर"** नामक स्टेट प्लान योजना वर्ष 2005–06 से लागू की गई है। इस स्कीम के अर्न्तगत वर्ष 2019–2020 तक कुल 953 रेन वाटर हारवैस्टिंग स्टरक्चरों का निर्माण किया गया है। बाढ़डा में वर्ष 2019–20 तक कुल 08 रेन वाटर हारवैस्टिंग स्टरक्चरों का निर्माण किया गया है।
3. विभाग द्वारा किसानों को टपका सिंचाई प्रणाली के उपयोग हेतू प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके अर्न्तगत 5 हैक्टेयर तक के लिये सभी श्रेणियों के किसानों हेतू 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 तक इस योजना के अर्न्तगत 4819.19 हैक्टेयर क्षेत्र में टपका सिंचाई प्रणाली हेतू 2943.00 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

   माह जुलाई, 2020 तक चरखी दादरी के बाढ़डा खण्ड में टपका सिंचाई प्रणाली के अर्न्तगत कुल 53 लार्भाथियों का 60.64 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने हेतू कुल 44.44 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।
4. विभाग द्वारा किसानों को फव्वारा सिंचाई प्रणाली के उपयोग हेतू भी प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके अर्न्तगत 5 हैक्टेयर तक के लिये सभी श्रेणियों के किसानों हेतू 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 तक इस योजना के

अर्न्तगत 674788.18 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयन्त्र प्रणाली हेतू 28636.03 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

माह जुलाई, 2020 तक चरखी दादरी के बाढ़डा खण्ड में फव्वारा संयन्त्र प्रणाली के अर्न्तगत कुल 1472 लार्भाथियों का 1826.35 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने हेतू कुल 473.98 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।

5. लीकेज तथा वाष्पीकरण से होने वाली हानि से बचने के लिये किसानों को भूमिगत पाईपलाईन प्रणाली के अर्न्तगत अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है जिसके अर्न्तगत प्रणाली की कीमत की 50 प्रतिशत जो कि 25000/– रूपये प्रति हैक्टेयर होता है तथा अधिकतम सीमा 60000/– रूपये तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 तक 223695.21 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाईपलाईन प्रणाली पर 35842.35 लाख रूपये खर्च किये गये।

   माह जुलाई, 2020 तक चरखी दादरी के बाढ़डा खण्ड में भूमिगत पाईपलाईन प्रणाली के अर्न्तगत कुल 265 लार्भाथियों का 501.69 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने हेतू कुल 93.00 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।

6. प्राकृतिक भू–जल संसाधन के संरक्षण हेतू राज्य में फसल विविधीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत धान जैसी अधिक सिंचाई वाली फसलों के स्थान पर मक्का, सूरजमुखी तथा समर मूंग जैसी कम सिंचाई वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा **"मेरा पानी मेरी विरासत"** नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अर्न्तगत किसानों को 7000/– रूपये प्रति एकड के हिसाब से किसानों को अनुदान देने का प्रावधान है।
7. भू–जल के उचित प्रयोग तथा संरक्षण हेतू किसानों को शिक्षित एवं अवगत करवाने के लिये विभाग द्वारा समय–समय पर बडे स्तर पर कैम्प भी लगाये जाते हैं।